

7 जून, 2024 को अटल भूजल योजना की छठी एनएलएससी बैठक

अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन के लिए 7 जून 2024 को राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) की छठी बैठक, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली, के सम्मेलन कक्ष में, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में अटल भूजल योजना के संचालन में शामिल सातों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, विश्व बैंक और एनपीएमयू के अधिकारी शामिल हुए।

संयुक्त सचिव (प्रशासन, आईसी एवं भूजल) और राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक, अटल भूजल योजना ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में इस बात पर जोर दिया कि यह योजना कार्यान्वयन के पांचवें एवं अंतिम वर्ष में है। इस वर्ष इस योजना का बेहतर उपयोग किया जाए ताकि इस योजना के परिणामों को अन्य क्षेत्रों में उदारणार्थ प्रदर्शित किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सामुदायिक भागीदारी ही योजना का मूलभूत पहलू है। राज्यों को योजना की गतिविधियों को इसके निर्धारित अंत से आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) की पहचान करनी चाहिए।

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सचिव ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में इस बात पर प्रकाश डाला कि अटल भूजल योजना एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो भूजल प्रबंधन के डिमांड-साइड को लक्षित करके समुदाय के व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने राज्यों को अटल जल के तहत शामिल गतिविधियों का आत्मनिरीक्षण करने और लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों को बढ़ाने के लिए शेष योजना अवधि का सर्वोत्तम उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने चयनित क्षेत्रों में योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए डेटा के उपयोग और विश्लेषण के महत्व और राज्यों को योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी भाग लेने वाले राज्यों से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) में जल सुरक्षा योजना (डब्ल्यूएसपी) को एकीकृत करने का अनुरोध किया ताकि समय अवधि पूरी होने के बाद भी योजना द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्थिरता प्रदान की जा सके।

समिति ने अटल जल योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा की और राज्यों को भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) के तहत प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए कंवर्जेंस सहित सभी गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया। एनपीएमयू द्वारा राज्यों की शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रभाव का आकलन और राज्यों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने पर संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिससे दिलचस्प जानकारी मिली।



अटल भूजल योजना द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) की छठी बैठक।



सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, छठी एनएलएससी बैठक के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।



श्री सुबोध यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन, आईसी एवं भूजल) और राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक, अटल भूजल योजना, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, छठी एनएलएससी बैठक के दौरान प्रतिभागियों को सम्बोधन करते हुए।